कागज़ का निर्यात

1412. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994-95 में कितना और कितनी राशि का कागज विदेशों को भेजा गया और किन-किन देशों को भेजा गया;

(ख) निर्यात किए गए कागज में अखबारी-कागज और वाईट पेपर की मात्रा कितनी-कितनी थी और मूल्य क्या-क्या था; और

(ग) इनको किन-किन दरों पर निर्यात किया गया था?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) नवीनतम आंकड़े अप्रैल, 1994 से फरवरी, 1995 तक के उपलब्ध है। इस अवधि के दौरान 78.63 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न प्रकार के 33,757 मी॰ टन कागज़ का निर्यात किया गया। देशवार आंकड़े डी.जी.सी.आई.एण्ड एस. द्वारा प्रकाशित "फारेन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया" में दिए गए हैं, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) उपर्युक्त निर्यात आंकड़ों में 8.64 करोड़ रुपये का 3608 मी॰ टन अखबारी कागज भी शामिल है। सफेद कागज के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) दरें अलग-अलग होती हैं जो गुणवत्ता, आकार, विशिष्टता और बाजार शक्तियों जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन

1413. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार उक्त संशोधन को संसद के सम्मुख कब ला रही है?

श्रम मंत्री (श्री पी॰ए॰ संगमा): (क) से (ग) नये औद्योगिक संबंध कानून संबंधी रामानुजम समिति द्वारा की गई सिफारिशों और विभिन्न मंचों पर किये गये विचार विमर्श के आधार पर तथा औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अंतर मंत्रालयीन ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के लिए उचित समय पर विचार-विमर्श करने और अंतिम रूप देने हेतु विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

Enhancement of Levy Sugar Allocated to States

1414. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to enhance the levy sugar allocation to different States in view of the comfortable stock position of sugar in the Central Pool;

(b) if so, the allocation of sugar made to different States at present;

(c) the percentage of increase proposed to be made in the allocation of sugar to different States;

(d) the date from which the allocation is proposed to be enhanced; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

The normal monthly allocation of sugar made to different States/UTs is given in the enclosed Statement *(see below)*.

(c) to (e) Central Government has decided to increase the allocations of levy sugar to all States/UTs by five per cent on an ad-hoc basis with effect from September, 1995. Such an ad-hoc five per cent increase in the allocation was given to the States/UTs earlier (from September, 1991 to March 1994) also.

Statement

Normal Monthly alloction of Sugar made to States/UTs

Sl. No.	State/UT	Normal monthly allocation
1.	Andhra Pradesh	25281
2.	Arunachal Pradesh	314
3.	Assam	9617
4.	Bihar	33459
5.	Gujarat	16194
6.	Goa	500
7.	Haryana	6386
8.	Himachal Pradesh	2019
9.	Jammu & Kashmir	3136
10.	Karnataka	17769
11.	Kerala	11953
12.	Madhya Pradesh	25031
13.	Maharashtra	29938
14.	Manipur	694
15.	Meghalaya	662
16.	Mizoram	261
17.	Nagaland	426
18.	Orissa	12393
19.	Punjab	7945
20.	Rajasthan	16914
21.	Sikkim	165
22.	Tamil Nadu	22547
23.	Tripura	1001
24.	Uttar Pradesh	52926
25.	West Bengal	25888
26.	A&N Islands	247
27.	Chandigarh	372
28.	D&N Haveli	51
29.	Daman & Diu	39
30.	Delhi	9921
31.	Lakshadweep	71
32.	Pondicherry	305
	Total	335972

नौवीं पंचवर्षीय योजना में विकास पर बल

1415. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विकास के लिए बनाए जाने वाली नौवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में विकास पर अधिक बल दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) से (ग) आठवीं योजना दस्तावेज में विकास सम्भावनाओं पर कार्य करते हुए यह कहा गया है कि लम्बी अवधि, जिसमें नौवीं योजना अवधि भी शामिल है, में विकास के पैटर्न और गति के माध्यम से ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र ये हैं;

(i) "खाद्य सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता और

(ii) एक विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रणाली की परिधि में जनसंख्या की सामाजिक आवश्यकताओं और न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता।

सरकार सामजिक सेक्टर को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

Proposal to reduce the price of Rice supplied through PDS

1416. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 137 given in the Rajya Sabha on 31st July, 1995 and state whether proposals are on the anvil to reduce the issue price of rice so as to encourage larger offtake from the Public Distribution System?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): There is no proposal to reduce the Central issue Prices of Rice and Wheat for the Public Distribution System. However, proposals to increase the special subsidy of Rs. 50/- per quintal allowed at present on foodgrains meant for distributiom in the areas under the Revamped Public Distribution System (RPDS) is under examination.